

गवर्नर का सीएनबीसी टीवी18 के साथ 23 मई, 2022 को हुए साक्षात्कार का संपादित प्रतिलेख

सीएनबीसी टीवी18

केंद्रीय बैंकर्स हमेशा कार्रवाई के केंद्र में रहे हैं, अर्थव्यवस्था के रक्षक; चाहे वह कोविड के क्रहर से बचाना हो या अब, महंगाई को तेज़ी से कम करना हो। भारतीय रिज़र्व बैंक भी देश के लिए सुरक्षा की पहली पंक्ति रहा है, और उसने 4 मई को अपनी यह स्थिति बहुत साफ़ कर दी थी, जब हमने दरों में वह अप्रत्याशित ऑफ-साइकिल बढ़ोतरी देखी थी। फिर भी, महंगाई 7.8 प्रतिशत पर है। हॉट सीट पर बैठे व्यक्ति, आरबीआई गवर्नर हमारे साथ हैं। गवर्नर साहब, हमारे लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

शक्तिकांत दास

धन्यवाद।

सीएनबीसी टीवी18

ऐसा लगता है कि 4 मई की आपकी पॉलिसी के बाद केंद्र और आरबीआई की ओर से सचमुच एक समन्वित और तालमेल वाली कार्रवाई हुई है। हमने देखा कि ईंधन की कीमतों और ईंधन पर एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती जैसे कई कदम उठाए गए। अब, महंगाई को लेकर आपका क्या अंदाज़ा है? आपको क्या लगता है कि हम उस 6 प्रतिशत और उससे नीचे के लक्ष्य तक कब पहुँच पाएँगे?

शक्तिकांत दास

सबसे पहले, आपने समन्वित कार्रवाई के बारे में जो बात कही, मैं उस पर यह कहना चाहूँगा कि मेरे नज़रिए से, हम महंगाई को काबू में करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक अधिकारियों के बीच समन्वित कार्रवाई के एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। आरबीआई ने पिछले दो-तीन महीनों में कई कदम उठाए हैं। असल में, मैं तो यह कहूँगा कि हम इससे भी काफी पहले से कदम उठाते आ रहे हैं, लेकिन किसी वजह से बाज़ार के कुछ हिस्सों ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया। और मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ: सरकार ने अब गेहूँ, बिचौलियों और अलग-अलग तरह के बिचौलियों - कच्चे माल पर, और ज़ाहिर है, पेट्रोल और डीज़ल पर भी बड़े कदम उठाए हैं। अब, इन सभी कदमों का मिला-जुला असर निश्चित रूप से महंगाई को काबू में करने में मददगार साबित होगा। आगे की बात करें तो, सप्ताहांत में पेट्रोल और डीज़ल पर कर में कटौती की घोषणा की गई है। और आरबीआई में, हम एक बार फिर से अपनी योजनाओं पर काम करने में जुट गए हैं। असल में, हम लगभग हर दिन ही अपनी योजनाओं पर काम करते रहते हैं। इसलिए, हम अपने आँकड़ों की फिर से समीक्षा करेंगे और जून के पहले हफ़्ते में होने वाली अगली एमपीसी बैठक में उन आँकड़ों को जारी करेंगे।

सीएनबीसी टीवी18

मैं आपसे यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने अर्थशास्त्रियों के बीच सीएनबीसी का एक पोल करवाया था। उनका मानना है कि 6 प्रतिशत का आंकड़ा चौथी तिमाही तक नहीं आएगा। यानी जनवरी-मार्च वाली तिमाही तक। तो ऐसा लगता है कि सीपीआई को 6 प्रतिशत से ऊपर रहने वाली तीन तिमाहियों का सामना करना पड़ेगा।

शक्तिकांत दास

अक्टूबर अभी काफी दूर है। इसलिए, अभी से कोई अंदाज़ा न लगाएं, इस बीच कुछ और कदम भी उठाए जा सकते हैं। आज मई का महीना है, अभी करीब पांच महीने बाकी हैं। तो, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं आज कोई आंकड़ा नहीं दे सकता क्योंकि हम अभी इस पर काम कर रहे हैं। जून में होने वाली अगली एमपीसी एमपीसी ही वह सही समय होगा जब हम बता पाएंगे कि हमारे हिसाब से महंगाई का अनुमान क्या है। पिछले साल, मोटे तौर पर, पेशेवर भविष्यवेत्ता के आंकड़े आरबीआई के आंकड़ों के साथ-साथ ही चलते थे। उनके आंकड़े कभी कम होते थे तो कभी ज़्यादा।

सीएनबीसी टीवी18

लेकिन अब तो ये आंकड़े साफ तौर पर ज़्यादा हैं, सर। पिछला आंकड़ा 5.7 प्रतिशत था।

ईंधन की कीमतों में कटौती से पहले, बाज़ार का औसत अनुमान 6.5 से 6.8 प्रतिशत के बीच था।

शक्तिकांत दास

मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल, या यूँ कहें कि इस साल फरवरी में, जब हमने 4.5 प्रतिशत का अनुमान दिया था - जिसे कई लोगों ने बहुत ज़्यादा आशावादी माना था - तो अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं आपको समझा सकता हूँ कि वह अनुमान ज़्यादा आशावादी क्यों नहीं था।

उस समय पेशेवर भविष्यवेत्ता का अनुमान करीब 5.0 प्रतिशत था। और बाद में, जब हमने अपना अनुमान बढ़ाकर 5.7 प्रतिशत किया, तो मुझे लगता है कि पेशेवर भविष्यवेत्ता का अनुमान भी 5.5 या 6.0 प्रतिशत के आसपास, या शायद 6.0 प्रतिशत से थोड़ा ज़्यादा था।

तो, दोनों के आंकड़े एक-दूसरे के साथ-साथ ही चल रहे हैं। इसलिए, आरबीआई के आंकड़े हम जून में जारी करेंगे। बिना आंकड़ों पर ठीक से काम किए और एमपीसी की बैठक से पहले, मेरे लिए अभी कोई आंकड़ा बताना सही नहीं होगा।

सीएनबीसी टीवी18

अब मैं ब्याज दरों और दरों में बढ़ोतरी के मुद्दे पर आता हूँ। जब आपने 4 मई को मौद्रिक नीति बयान देते हुए अपना भाषण दिया था - और अगर मैं डॉ. पात्रा की बैठक के मिनिट्स

(कार्यवृत्त) पढ़ें - तो ऐसा लगता है कि आप यह संकेत देना चाह रहे थे कि आप जल्द से जल्द 5.15 प्रतिशत के स्तर पर पहुंचना चाहते हैं; यानी, कोविड से पहले वाले स्तर पर। क्या हमने आपकी बात सही समझी है कि आप अगस्त तक उस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं?

शक्तिकांत दास

मोटे तौर पर, आप इस हद तक सही हैं कि आरबीआई अगली कुछ बैठकों में, या कम से कम अगली बैठक बैठक में तो दर दर बढ़ाना चाहेगा। मैंने खुद अपने कार्यवृत्त में कहा है कि मई में नियमित अंतराल से इतर बैठक का एक कारण यह था कि हम जून में कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते थे, जिससे बचा जा सकता था। आप 75 या 100 धार अंक आधार अंक, या 80 आधार अंक - कुछ इस तरह से दर कम नहीं कर सकते। ये जो नंबर मैं बता रहा हूँ - 75, 100, या 80 - ये बस ऐसे ही रैंडम नंबर हैं; कृपया इन नंबरों का गलत मतलब न निकालें।

सीएनबीसी टीवी18

लेकिन आपने 'प्री-कोविड' (कोविड से पहले का समय) का उल्लेख उल्लेख किया था, और इसीलिए यह 5.15 का आँकड़ा सामने आया।

शक्तिकांत दास

'प्री-कोविड' की बात मैंने चलनिधि चलनिधि और ब्याज दर - दोनों के ही एक बड़े संदर्भ में कही थी। अगर आप मेरे मिनट्स ध्यान से पढ़ें, तो जब हम 'प्री-कोविड' कहते हैं, तो हमारा मतलब होता है - विकास के मामले में कोविड-पूर्व का स्तर; चलनिधि के मामले में प्री-कोविड स्तर; और दर के मामले में भी प्री-कोविड स्तर। इसलिए, दर में बढ़ोतरी की उम्मीद तो बिल्कुल साफ़ है - रेपो दर में कुछ न कुछ बढ़ोतरी जरूर होगी। हाँ, यह बढ़ोतरी कितनी होगी - यह मैं अभी नहीं बता सकता; लेकिन यह कहना कि यह आँकड़ा 5.15 ही होगा -शायद पूरी तरह से सही न हो।

सीएनबीसी टीवी18

पात्रा के बयान में कहा गया था कि अगर हम कोविड कोविड से पहले के स्तर पर पहुँच जाएँ, तो हम भी न्यूट्रल स्थिति में पहुँच जाएँगे; इसीलिए 5.15 का आँकड़ा, जिसे बाज़ार बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा है।

शक्तिकांत दास

एमपीसी में हमारी बहुत सारी चर्चाएँ और विचार-विमर्श होते हैं, और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं।

सीएनबीसी टीवी18

चलिए, अब चलनिधि वाले हिस्से पर आते हैं। आपने अभी-अभी उल्लेख किया कि आप कोविद से पहले वाले स्तरों पर वापस आना चाहते हैं। अब, कोविद से पहले का चलनिधि स्तर - मान लीजिए फरवरी या जनवरी 2020 का - ढाई लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त चलनिधि वाला था। करेंसी और फाइनेंस की रिपोर्ट कहती है कि ढाई लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की चलनिधि होने पर महँगाई बढ़ने लगती है। तो, क्या आप भी तेज़ी से उस ढाई लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँचना चाहते हैं?

शक्तिकांत दास

मैं समझाता हूँ। हमने कहा है कि हम कई सालों के समय-चक्र में चलनिधि की स्थितियों को सामान्य करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने कहा था कि यह कई सालों का समय-चक्र दो साल का भी हो सकता है, या तीन साल का भी। अब, हम किस हद तक और किस तरह से चलनिधि को कम करेंगे, यह विकास और महँगाई के बदलते समीकरणों पर निर्भर करेगा; यह हमारी रणनीति का ही एक हिस्सा है। दूसरी बात है चलनिधि की ज़रूरत, या चलनिधि की पर्याप्तता। 2019-20 की चलनिधि की पर्याप्तता, मौजूदा साल की चलनिधि की पर्याप्तता से अलग होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है और कारोबारी गतिविधियाँ भी अब फिर से ज़ोर पकड़ रही हैं। इसलिए, यह आँकड़ा बदलता रहेगा। चलनिधि पर हमारा रुख यह है कि हम चलनिधि को सामान्य करना चाहते हैं, सिस्टम में मौजूद अतिरिक्त चलनिधि के बोझ को हटाना चाहते हैं, और एक ऐसी स्थिति में पहुँचना चाहते हैं जहाँ अर्थव्यवस्था की उत्पादक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सिस्टम में पर्याप्त क्रेडिट (ऋण) उपलब्ध हो; साथ ही, जब क्रेडिट की माँग बढ़े, तो उसे भी पूरा किया जा सके - क्योंकि जब क्रेडिट की माँग बढ़ती है, तो चलनिधि का कुछ हिस्सा उसमें भी खप जाता है। इसलिए, हमारा लक्ष्य दो से तीन साल की समय-सीमा के भीतर अतिरिक्त चलनिधि के बोझ को पूरी तरह खत्म करना है, और साथ ही, सिस्टम के लिए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करना भी है।

सीएनबीसी टीवी18

ओवरहैंग शायद एक ट्रिलियन रुपये तक होगा या फिर चलनिधि ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन यह ढाई ट्रिलियन रुपये - करेंसी और फाइनेंस की मौजूदा रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे महँगाई बढ़ सकती है। इसीलिए मैं जानना चाहता था कि क्या वहाँ तक पहुँचने की ज़्यादा जल्दी है। साथ ही, आपने सीआरआर सीआरआर भी बढ़ाया है; आप एनडीएस सरकारी बॉन्ड बेच भी रहे हैं, भले ही छोटी मात्रा में - ये सभी चलनिधि कम करने वाले कदम हैं, और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या शुरुआती कदम थोड़े तेज़ होंगे।

शक्तिकांत दास

नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। एनडीएस-ओएम बाज़ार में यह बीच-बीच में किया जाने वाला दखल असल में चलनिधि सोखना नहीं है। यह वहाँ से नहीं आ रहा है। बाज़ार में कई तरह के

पेचीदा घटनाक्रम हो रहे हैं और समय-समय पर हम कई तरह के जटिल कारणों से दखल देते रहते हैं। चलनिधि की वापसी के बारे में, अगर आपको याद हो, तो मेरे पहले के एक बयान में मैंने कहा था कि पिछले अनुभवों से सीखते हुए, हम चलनिधि दुष्चक्र से बचना चाहते हैं। हम बिना बाहर निकलने का रास्ता जाने किसी 'चक्रव्यूह' जैसी स्थिति में नहीं फंसना चाहते। इसलिए, हमारी चलनिधि बढ़ाने की जितनी भी कोशिशें थीं - चाहे वह टीएलटीआरओ हो या कुछ और - उन सबकी एक तय आखिरी तारीख थी। उदाहरण के लिए, हमने कुल मिलाकर करीब 17 लाख करोड़ रुपये की चलनिधि मदद का ऐलान किया था, जिसमें से असल में करीब 12 लाख करोड़ रुपये ही लिए गए, और उसमें से भी 5 लाख करोड़ रुपये पहले ही वापस आ चुके हैं। बाकी बचे करीब 7 लाख करोड़ रुपये अभी भी सिस्टम में मौजूद हैं। इसमें से, ओवरनाइट एसडीएफ के ज़रिए हमें करीब 2 लाख करोड़ रुपये वापस मिल जाते हैं, और बाकी रकम वीआरआरआर वीआरआरआर के तहत एक खास हिस्से में मौजूद है। इसलिए, हम इस रकम को कम करेंगे, लेकिन बहुत ही सोच-समझकर और धीरे-धीरे, अलग-अलग चरणों में।

सीएनबीसी टीवी18

चलिए, अब मैं फिर से दरों के मुद्दे पर आता हूँ। मुझे लगता है कि बैठक की कार्यसूची में से किसी एक में आशिमा गोयल ने कहा था कि बाज़ार बाज़ार में दरों में बढ़ोतरी को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, वे कुछ ज़्यादा ही हैं। अभी, स्वैप बाज़ार में दरों को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे थे, उनके हिसाब से रेपो रेट की ऊपरी सीमा (peak) करीब 6.75% तक जा सकती है - क्या आपको भी लगता है कि यह अनुमान कुछ ज़्यादा ही है?

शक्तिकांत दास

मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। स्वैप बाज़ार की अपनी एक गति होती है और उसे प्रभावित करने वाले अपने अलग कारक होते हैं। असल में, मुझे तो यह उम्मीद है कि स्वैप बाज़ार और पूरा बाज़ार, रिज़र्व बैंक के बयानों और उसके द्वारा उठाए गए कदमों से ही दिशा लेगा। मैं यहां यह भी बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि पिछले दो सालों में - खासकर कोविड महामारी के दौरान जब हालात बेहद मुश्किल थे - आरबीआई और वित्तीय बाज़ार के बीच एक तरह की आपसी समझ बन गई थी। कई मामलों में दोनों की सोच और नज़रिए में काफी हद तक एकरूपता देखने को मिली थी। इसी तरह हम आज उस मुकाम तक पहुँच पाए हैं, जहाँ आर्थिक गतिविधियों में सुधार स्थिर हो गया है और इसमें और तेज़ी आ रही है।

सीएनबीसी टीवी18

फिर भी, महँगाई एक मुद्दा है। इस बात की पूरी संभावना है कि अगले तीन तिमाहियों तक हम 6.0 प्रतिशत से नीचे नहीं जाएँगे; यह 6.0 प्रतिशत से ऊपर ही रहेगा। इसीलिए बाज़ार यह जानना चाहेगा कि आप दरों को किस नज़रिए से देख रहे हैं। मौद्रिक नीति परिषद के एक सदस्य ने सकारात्मक वास्तविक दरों, या कम से कम शून्य वास्तविक दरों तक पहुँचने की

ज़रूरत के बारे में बात की थी; अभी हम काफी ज़्यादा नकारात्मक स्थिति में हैं - आप 4.4 प्रतिशत पर हैं, जबकि महँगाई सात प्रतिशत से काफी ऊपर चल रही है। हम काफी ज़्यादा नकारात्मक स्थिति में हैं। क्या आप भी सकारात्मक, या कम से कम शून्य वास्तविक दरों पर लौटने की ज़रूरत महसूस करते हैं?

शक्तिकांत दास

आज महँगाई चिंता का एक बड़ा विषय है; देश में हर किसी के लिए यह एक अहम मुद्दा है। इसलिए, मैं इसे विस्तार से समझाना चाहूँगा और शायद इसमें सामान्य से थोड़ा ज़्यादा समय लूँगा। शुरुआत में मैं दो बातें बताना चाहूँगा। पहली बात, आज लगभग हर देश में ब्याज दरें नकारात्मक (शून्य से नीचे) हैं, शायद रूस और ब्राज़ील को छोड़कर। इनके अलावा, आप किसी भी उन्नत अर्थव्यवस्था को देखें, या किसी और को, वहाँ ब्याज दरें नेगेटिव दायरे में हैं। दूसरी बात यह है कि महँगाई के मामले में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए लक्ष्य, उदाहरण के लिए, 2 प्रतिशत है; अमरीका में यह 8.3 प्रतिशत है; यूनाइटेड किंगडम में 9 प्रतिशत है; और यूरो क्षेत्र में 7 प्रतिशत से ज़्यादा है। मुझे लगता है कि जापान और एक और देश को छोड़कर, बाकी सभी जगह यह 7 प्रतिशत से ज़्यादा है। भारत में, हमारा लक्ष्य 4 प्रतिशत है और हमारे पास एक 'टॉलरेंस बैंड' (स्वीकार्य सीमा) है जो 6 प्रतिशत तक जाता है; अभी हम 7.8 प्रतिशत पर हैं। बाज़ार में कुछ विश्लेषक ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अपने चरम (peak) पर पहुँच चुके हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि यह फिर से कई अन्य कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम भी शामिल हैं। अगर आप मुझे थोड़ा और समय दें, तो मुझे लगता है कि इससे शायद आपके मन में उठने वाले कई सवालों का जवाब पहले ही मिल जाएगा। महँगाई के उस अधिदेशित-लक्ष्य को देखें, जो 'भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम' के तहत आरबीआई को सौंपा गया है। यह एक 'दोहरा लक्ष्य' है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कीमतों में स्थिरता बनाए रखी जाए। कीमतों में स्थिरता का मतलब है 4 प्रतिशत, जिसमें दोनों तरफ 2 प्रतिशत की घट-बढ़ की गुंजाइश हो, और यह सब आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाए। इसलिए, जब 2020 की पहली तिमाही में - जब कोविड का प्रकोप शुरू हुआ था - हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तब हम -24 प्रतिशत पर थे। और उस साल (2020) पूरी अर्थव्यवस्था- 6.6 प्रतिशत पर रही थी। साल 2021-22 के लिए अंतिम आंकड़े 31 तारीख को जारी किए जाएंगे। लेकिन हमें यह एहसास है कि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई है, यह आगे बढ़ी है, भले ही थोड़ी ही सही। यह महामारी से पहले के स्तर से आगे निकल गई है और 2019-20 के स्तरों को भी पार कर गई है। निजी खपत अब सकारात्मक दायरे में आ गई है। निजी निवेश में भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं। इसलिए, उस समय हमारा मुख्य लक्ष्य विकास पर ध्यान देना और महँगाई को वापस 6 प्रतिशत तक के सहनीय स्तर पर लाना था। इस दौरान बीच-बीच में, महँगाई बढ़कर 6 प्रतिशत और उससे ऊपर चली गई। एक या दो मौकों पर, यह 7 प्रतिशत तक भी पहुँच गई। लेकिन

पिछले साल, जब मैं आँकड़े देख रहा था, तो कई मौकों पर महंगाई लगभग 4 प्रतिशत तक नीचे आ गई थी, और अगर मुझे ठीक से याद है, तो ऐसा जनवरी में हुआ था, फिर अप्रैल के आसपास भी ऐसा ही हुआ। और फिर, शायद सितंबर और अक्टूबर में भी, यह घटकर 4 प्रतिशत पर आ गई थी। हमने इसे अस्थायी कारणों से होने वाली महंगाई कहना बंद कर दिया था। मौजूदा महंगाई के लिए भी आपूर्ति-पक्ष के कारक ही मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। लेकिन हमने इसे अस्थायी कहना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हम इस नतीजे पर पहुँच गए थे कि यह इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। अब, जब हमने इस कैलेंडर वर्ष में प्रवेश किया, तो असल में यह सवाल पूछा गया था, और मैंने सोचा कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर व्यापक समझ के लिए इसे स्पष्ट कर दूँ। सवाल पूछे गए हैं, और मैंने फरवरी में भी पहले इसका उल्लेख किया था। महंगाई को लेकर हमारा एमपीसी अनुमान आशावादी बना हुआ है; मैं आपको बताता हूँ कि हमने 4.5 प्रतिशत का अनुमान क्यों लगाया था। अक्टूबर से लेकर हर महीने, महंगाई की रफ़्तार धीमी पड़ रही थी। खाने-पीने की चीज़ों की महंगाई कम हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कोविड का असर कम होने के साथ आपूर्ति-श्रृंखला की रुकावटें दूर होने लगेंगी, आपूर्ति-पक्ष के कारक अपने आप ही ठीक हो जाएँगे। फरवरी में भी, हमने अपने स्ट्रेस टेस्ट किए थे, हमने अपने परिदृश्य विश्लेषण किए थे। हमने पाया कि 50 आधार अंकों की त्रुटि की गुंजाइश के साथ भी, हम 5.0 प्रतिशत के स्तर पर रहेंगे। हमने कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर से थोड़ी कम मानी थीं, और उसके आधार पर हमारी महंगाई का अनुमान लगभग 5.0 प्रतिशत आया था। हम काफी हद तक सहज थे और भविष्य के लिए हमारा रोडमैप यह था कि महंगाई कम होगी। लेकिन फिर फरवरी में, 24 फरवरी को युद्ध शुरू हो गया; और सब कुछ बदल गया। अप्रैल में, जब हमारी एमपीसी की बैठक हुई, तो हमने कई निर्णायक कदम उठाए; हमने अपनी प्राथमिकताओं का क्रम बदल दिया, और हमने महंगाई को पहली और विकास को दूसरी प्राथमिकता दी। हमने अपने LAF कॉरिडोर को सामान्य किया। हमने अपना रुख बदलते हुए कहा कि हम 'अकोमोडेशन' (नरमी) को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, और इसके तहत हमने दरों में बदलाव किया। दरों में बदलाव यह था कि हमने एसडीएफ एसडीएफ को लागू किया, और 3.35 प्रतिशत के रिवर्स रेपो रेट के मुकाबले, एसडीएफ को 3.75 प्रतिशत पर तय किया गया - यानी, 40 आधार अंक की बढ़ोतरी। अब, चलनिधि सोखने की दर में इस 40 आधार अंक की बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप, ओवरनाइट कॉल दर में तत्काल 40 आधार अंक की वृद्धि हो गई। तो, इस तरह दरों में बदलाव किया गया था। बाजार और सभी लोगों को इस बात पर गौर करना चाहिए कि अप्रैल महीने में ही दरों में बदलाव किया गया था - एक ऐसी बात, जिसे शायद कई लोग नज़रअंदाज़ कर गए हैं। इसलिए, यह सवाल कि अचानक बैठक क्यों बुलाई गई, आदि- तो यह बैठक अचानक नहीं हुई थी। अप्रैल में, हमने दरों में 40 आधार अंक का बदलाव किया था, और ओवरनाइट दर में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी हुई थी। एमपीसी की बैठक के बाद, कई नए घटनाक्रम सामने आए- उदाहरण के लिए, एफएओ और विश्व बैंक की रिपोर्टें।

सीएनबीसी टीवी18

ठीक है, आपने अपना बचाव किया है, लेकिन आपने मुझे यह नहीं बताया कि क्या आप जल्द ही सकारात्मक वास्तविक दर पर आना चाहते हैं?

शक्तिकांत दास

हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह कितनी जल्दी होगा, यह बदलती हुई स्थिति पर निर्भर करेगा, और मेरी तरफ से इस बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा। असल में, यह अनुमान लगाना मुमकिन भी नहीं है कि ऐसा कितनी जल्दी होगा, क्योंकि स्थिति बहुत तेज़ी से बदल रही है। उदाहरण के लिए, हमारे कदमों और सरकार द्वारा सही समय पर उठाए गए कदमों की वजह से महंगाई के आंकड़ों में बदलाव आता है।

सीएनबीसी टीवी18

गवर्नर साहब, आपने उन कदमों के बारे में बात की है जो केंद्र सरकार ने अब उठाए हैं। लेकिन इन कदमों का असर राजकोषीय घाटे पर पड़ेगा, और शायद चालू खाता घाटे पर भी। राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होगी और शायद बाज़ार से कर्ज़ भी लेना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि उन्हें और ज़्यादा कर्ज़ लेना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कर से होने वाली कमाई में से लगभग तीन ट्रिलियन रुपये की छूट दे दी गई है।

शक्तिकांत दास

ज़ाहिर है, मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल सकता। लेकिन वित्त मंत्रालय में काफी लंबे समय तक काम करने के अनुभव के आधार पर, मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी एक मद के तहत सरकारी खर्च में बढ़ोतरी और अतिरिक्त कर्ज़ लेने की ज़रूरत के बीच कोई सीधा-सीधा संबंध नहीं होता। ये सभी आंकड़े साल भर बदलते रहते हैं। जैसे-जैसे साल आगे बढ़ता है, कृपया याद रखें कि अभी हम सिर्फ मई के महीने में हैं, जो मौजूदा वित्त वर्ष का दूसरा महीना है। कुछ मदों में खर्च की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, तो कुछ मदों में खर्च की ज़रूरतें या खर्च करने की क्षमता कम हो सकती है। कमाई के मामले में भी ऐसा ही हो सकता है। कमाई में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। असल में, कमाई के मौजूदा आंकड़े—या जीएसटी और प्रत्यक्ष कर के हालिया अनुभव को देखते हुए - काफी मज़बूत नज़र आ रहे हैं।

मेरा मानना है कि सरकार अपने वादे पर कायम है। मैं सच कहूँ तो सरकार की तरफ से नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि सरकार बजट में तय किए गए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखेगी। वे ऐसा कैसे करेंगे, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। लेकिन अपनी कई चर्चाओं से मुझे जो आभास हुआ है - और यह रिज़र्व बैंक तथा सरकार के बीच एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है—उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार राजकोषीय घाटे को संभालने के लिए एक तरह से प्रतिबद्ध होगी।

सीएनबीसी टीवी18

इसके बावजूद, 10-साल के बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़कर 7.4 तक पहुँच गई है, और संभावना है कि जैसे-जैसे सरकारी कार्यक्रम में तेज़ी आएगी और क्रेडिट की मांग बढ़ेगी, यह 8.0 प्रतिशत के स्तर तक भी पहुँच सकती है। अब, आपने एक बार सीआरआर बढ़ाया है, आप डॉलर और बॉन्ड बेच रहे हैं। तो, क्या आपको लगता है कि ओपन बाज़ार खरीद के ज़रिए सरकार की मदद करने की कोई गुंजाइश बची है?

शक्तिकांत दास

आरबीआई, सरकार का ऋण प्रबंधक है, और प्रतिफल वक्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई अपने पास उपलब्ध सभी साधनों का उपयोग करेगा। यह बात मैंने पहले भी कही थी। मुझे लगता है कि अक्टूबर 2020 में, मैंने कहा था कि प्रतिफल कर्व का प्रबंधन एक सार्वजनिक हित का विषय है, जिसमें बाज़ार और केंद्रीय बैंक, दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने पहले भी उस तरह के समझौते का उल्लेख किया था, जो हमने किया था। पूरी दुनिया में प्रतिफल बढ़ी है। और ऐसा कई जटिल कारकों के कारण हुआ है; मैं उन विस्तारों में नहीं जाऊँगा। हर जगह प्रतिफल बढ़ी है। अमरीका का प्रतिफल, जो 1 प्रतिशत से भी कम था, आज लगभग 3 प्रतिशत के स्तर को छू रहा है - बल्कि 3 प्रतिशत से ऊपर निकल गई थी। अब, यह लगभग 2.8 या 2.9 प्रतिशत के स्तर पर है। तो, हर जगह प्रतिफल बढ़ी है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से हमारे देश में भी प्रतिफल बढ़ी है। आरबीआई विभिन्न नीतिगत साधनों का उपयोग करेगा।

सीएनबीसी टीवी18

जिसमें ओएमओ भी शामिल हैं?

शक्तिकांत दास

मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा। हमारे पास कई तरह के नीतिगत साधन उपलब्ध हैं। हमारे पास 'ऑपरेशन ट्विस्ट' है। हमारे पास 'करेंसी स्वैप' की सुविधा है - जो चलनिधि प्रबंधन का एक और साधन है, जिसे हमने तीन साल पहले शुरू किया था। अगर आपको याद हो, तो हमारे पास ऐसे कई अन्य साधन भी हैं, जिनका हम उपयोग करेंगे और स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। हम अभी मौजूदा वर्ष के दूसरे महीने में ही हैं। हम स्थिति पर पूरी नज़र रखे हुए हैं, और बाज़ार के साथ मेरा जो अनौपचारिक समझौता है, मुझे लगता है कि वह जारी रहेगा। हम बाज़ार के साथ लगातार संवाद बनाए रखेंगे। आरबीआई, सरकारी उधार कार्यक्रम को बिना किसी बाधा के पूरा करने और प्रतिफल वक्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएनबीसी टीवी18

लेकिन क्या यह चिंता की कोई बात है, सर?

शक्तिकांत दास

हम ज़रूरत के हिसाब से समय-समय पर अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करेंगे।

सीएनबीसी टीवी18

लेकिन बाज़ार खुला बाज़ार परिचालन को एक तरीके के तौर पर देखने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है; यह मुख्य रूप से बाज़ार को प्रभावित करने वाला तरीका है।

शक्तिकांत दास

मैं खुद को सिर्फ़ ओएमओ तक सीमित नहीं रखना चाहता, जैसा कि आपने कहा। हमारे पास सभी तरीके मौजूद हैं; हम तय करेंगे कि किस तरीके का इस्तेमाल कहाँ करना है।

सीएनबीसी टीवी18

लेकिन कुल मिलाकर, क्या दोहरे घाटे के बिगड़ने की कोई चिंता है? यह काफ़ी मुमकिन है कि घाटा 6.4 से थोड़ा ज़्यादा हो जाए। शायद हम बच जाएँ, क्योंकि ज़्यादा महंगाई की वजह से नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा रहने की उम्मीद है। लेकिन, फिर भी, राजकोषीय घाटा बेहतर नहीं हो रहा है। इसी तरह, चालू खाता घाटा 3 प्रतिशत या उससे ज़्यादा रहने की उम्मीद है, और अब हम असल में स्टील जैसी चीज़ों के निर्यात को हतोत्साहित कर रहे हैं। क्या यह चिंता की बात है कि मैक्रो-इकोनॉमिक हालात बिगड़ रहे हैं?

शक्तिकांत दास

नहीं, मुझे लगता है कि निर्यात बहुत मज़बूत रहेगा। राजकोषीय घाटे के बारे में मैंने कहा है कि मेरा मानना है कि सरकार राजकोषीय घाटे को काबू में रखेगी। चालू खाता घाटा, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम इस साल चालू खाता घाटे को बहुत आसानी से संभाल लेंगे। भारत का बाहरी क्षेत्र मज़बूत बना हुआ है। मुझे लगता है कि लगातार 14वें महीने निर्यात 30 बिलियन अमरीकी \$ से ज़्यादा रहा है। और ताज़ा आँकड़ा 40 बिलियन अमरीकी \$ था। इसलिए, निर्यात क्षेत्र लगातार बहुत मज़बूत बना हुआ है। संयोग से आयात में भी तेज़ी आई है, और आयात में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था की बुनियादी मज़बूती को दिखाती है; इसका मतलब है कि माँग में तेज़ी आई है - यहाँ तक कि ज़्यादा कीमतों पर भी आयात जारी है - जिसका मतलब है कि घरेलू माँग फिर से बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि मैंने यह बात बहुत साफ़ कर दी है। घरेलू माँग फिर से बढ़ रही है और ज़्यादा कीमतों के

बावजूद आयात जारी है। इसलिए, घरेलू माँग में यह तेज़ी एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। हमारे पास फिएमआई के आंकड़े हैं, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के; ये विस्तार के दायरे में हैं। असल में, अप्रैल के आंकड़े पिछले आंकड़ों से ज़्यादा थे। मॉनसून अंडमान द्वीप समूह तक पहुँच चुका है और मुझे लगता है कि जल्द ही यह भारत के तटों, खासकर केरल तक पहुँच जाएगा और फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। तो, मॉनसून अच्छा दिख रहा है। कृषि भी अच्छी दिख रही है। जहाँ तक अनाज के भंडार की बात है, जिस पर इतनी चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि चावल का भंडार बफर स्टॉक से चार गुना ज़्यादा है और गेहूँ का भंडार, अगर मुझे ठीक से याद है, तो बफर लेवल से लगभग 1.8 गुना ज़्यादा है। इसलिए, भारत इस स्थिति से निपटने के लिए काफी अच्छी स्थिति में है। अर्थव्यवस्था के घरेलू बुनियादी पहलू मज़बूत हैं और बाहरी क्षेत्र भी मज़बूत बना हुआ है। एफडीआई का प्रवाह स्थिर है और कुछ नरमी के बावजूद, मुझे लगता है कि हाल के महीनों में, इन बुनियादी पहलुओं और इस तथ्य को देखते हुए कि हमारा बाहरी क्षेत्र मज़बूत है और हमारा कुल बाहरी कर्ज़ केवल 20 या 21 प्रतिशत के आसपास है, मुझे चालू खाता घाटे में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। आंकड़ा जो भी हो, हमें साल के आखिर में पता चल जाएगा; हम चालू खाता घाटे की भरपाई करने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में हैं।

सीएनबीसी टीवी18

सितंबर के बाद से, काफी लंबे समय में पहली बार, हमारा व्यापार घाटा हर महीने 20 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। ऐसा लगता है कि अगर हर महीने व्यापार घाटा 20 अरब डॉलर रहता है, तो साल भर में यह 240 अरब डॉलर हो जाएगा; और अगर हम अन्य सेवाओं और सॉफ्टवेयर भुगतानों के मद में 100 अरब डॉलर भी जोड़ लें, तो हम शायद 100 अरब डॉलर के चालू खाता घाटे की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं, पूँजी खाते पर, एफआईआई का बहिर्प्रवाह काफी गंभीर है। बाज़ार के लगभग हर अर्थशास्त्री को भुगतान संतुलन में घाटे की आशंका है; ऐसे में, क्या रुपया हमारे लिए चिंता का विषय है?

शक्तिकांत दास

चालू खाता घाटा तो होगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे सामने भुगतान संतुलन में घाटे जैसी कोई स्थिति आएगी। स्थिति लगातार बदल रही है। निर्यात बढ़ रहे हैं, और अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार बहुत मज़बूत हैं। आप सही कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में चालू खाता घाटा 20 बिलियन अमरीकी \$ तक पहुँच गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, भले ही यह उस स्तर तक पहुँच जाए जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं - 100 या 120 बिलियन अमरीकी \$ - मुझे लगता है कि हम आसानी से इसकी फ़ाइनेंसिंग कर पाएँगे। जहाँ तक रुपये को लेकर चिंताओं की बात है, तो मैं एक बात साफ़ कर दूँ: हमारी घोषित स्थिति यह है कि हम रुपये में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को रोकेंगे, और हम ऐसा करते रहेंगे। ज़ाहिर है, हम रुपये को तेज़ी से और बेकाबू होकर गिरने नहीं देंगे। रुपया अपना सही स्तर खुद तय

करेगा; हमारे मन में एक्सचेंज रेट (विनिमय दर) का कोई तय लक्ष्य नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। यह आरबीआई का घोषित रुख है।

सीएनबीसी टीवी18

लोग 77.50 के स्तर के बारे में बातें कर रहे थे।

शक्तिकांत दास

लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं यह बात आरबीआई की तरफ से कह रहा हूँ। आप मुझे ही 'असली सूत्र' मान सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे मन में कोई तय स्तर नहीं है। रुपये का मूल्य बाज़ार द्वारा ही तय होता है। लेकिन हम इसमें अत्यधिक उतार-चढ़ाव को ज़रूर रोकेंगे। हम रुपये को बेकाबू होकर गिरने नहीं देंगे। रुपया अपना सही स्तर खुद तय करेगा। और जहाँ तक कुछ लोगों या कुछ तबकों द्वारा जताई गई इस चिंता की बात है कि हमारे रिज़र्व (भंडार) कम हो रहे हैं, तो ज़रा इस पर गौर कीजिए: हम रिज़र्व क्यों बनाते हैं? हम रिज़र्व इसलिए बनाते हैं ताकि मुश्किल हालात से निपट सकें - ठीक वैसे ही हालात जिनका सामना हम अभी कर रहे हैं। तीन साल पहले, हमारे रिज़र्व 400 बिलियन अमरीकी \$ से भी कम थे; फिर हम 640 बिलियन अमरीकी \$ के स्तर तक पहुँचे। अब, हम 600 बिलियन अमरीकी \$ से थोड़ा नीचे हैं। ये जो 40 बिलियन अमरीकी \$ कम हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने रुपये को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने के लिए 40 बिलियन अमरीकी \$ बेच दिए हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा रिज़र्व के पुनर्मूल्यांकन के कारण है, क्योंकि जैसे-जैसे डॉलर मज़बूत होता है, वैसे-वैसे रिज़र्व के पुनर्मूल्यांकन के चलते आपके रुपये की कीमत गिरती है; इसलिए यह आरबीआई के हस्तक्षेप और रिज़र्व के पुनर्मूल्यांकन, दोनों का नतीजा है। फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई सरकारी राज़ नहीं खोल रहा हूँ। बाज़ार में हमारा हस्तक्षेप कई तरीकों से होता है, जिसका मकसद डॉलर के असल बहिर्प्रवाह को कम करना होता है, और मैं अपनी बात यहीं खत्म करूँगा।

सीएनबीसी टीवी18

आपका लाभांश 10 साल के सबसे निचले स्तर पर था। आखिरी बार, जब मैंने सुना था, तो यह 30,000 के स्तर पर सुबबाराव के कार्यकाल के दौरान था। तब सरकार ने इस पर कोई नाराज़गी नहीं जताई थी!

शक्तिकांत दास

जब लाभांश ज़्यादा होता है, तो आप पूछते हैं कि यह इतना ज़्यादा क्यों है; और जब यह कम होता है, तो आप पूछते हैं कि यह कम क्यों है?

सीएनबीसी टीवी18

मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ कि, आम तौर पर, क्या सरकार इस पर नाराज़गी नहीं जताती?

शक्तिकांत दास

में आपको बताता हूँ। लाभांश का आँकड़ा तुलनपत्र(बैलेंस शीट) पर निर्भर करता है। यह बैलेंस शीट से ही निकाला जाता है। साल के आखिर में जो भी सरप्लस (बचत) बचता है, उसे अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इसलिए, इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। आरबीआई का भी इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि 31 मार्च को हमारी स्थिति क्या है।

सीएनबीसी टीवी18

सर, रुपए की गिरावट और उसकी कीमत पर बस एक बात। क्या रिज़र्व बैंक जब विनिमय दर देखता है, तो चीन या युआन भी एक अहम बात होती है? क्योंकि चीनी युआन के मज़बूत होने के बावजूद, पिछले आठ हफ्तों में गिरने से पहले यह 6.3 तक पहुँच गया था। इस गिरावट के बावजूद, चीन के साथ हमारा घाटा बढ़ रहा है। तो, क्या यह भी कोई ऐसी चीज़ है जिस पर आप तब नज़र रखते हैं जब आप एक्सचेंज रेट देख रहे होते हैं?

शक्तिकांत दास

हम सभी करेंसी पर नज़र रखते हैं। हम युआन पर नज़र रखते हैं। हम सभी रिज़र्व करेंसी पर नज़र रखते हैं, हम उभरते बाज़ारों की करेंसी पर भी नज़र रखते हैं, और मुझे लगता है कि रुपया उभरते बाज़ारों की कई करेंसी से कहीं बेहतर रहा है। कुछ दिनों में, हो सकता है कि दूसरी करेंसी ने अच्छा प्रदर्शन किया हो। एक और बात जो मैं बताना चाहूँगा, वह यह है कि कुछ दिनों या एक-दो दिनों के लिए, कहीं किसी अचानक हुई घटना की वजह से रुपया गिर सकता है, लेकिन दिन के आखिर तक या अगले दिन तक, रुपया उसी स्तर पर वापस आ जाता है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। इसलिए, मैं यह कहना चाहूँगा कि रुपया काफ़ी स्थिर रहा है, और हम इसकी स्थिरता सुनिश्चित करेंगे।

सीएनबीसी टीवी18

बाज़ार में, हम आमतौर पर कहते हैं कि भगवान ने काम किया है। यानी, रुपया वापस आ गया है। भगवान से उनका मतलब सिर्फ़ आरबीआई होता है, जब वे कहते हैं कि भगवान ने काम किया है और हमारा रुपया वहीं वापस आ गया है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। ज़्यादा अहम बात यह है कि जब आप आईएमएफ गए थे, जब आरबीआई की टीम आईएमएफ गई थी, और जब आप सब वापस आए, तो अचानक 2-4 मई को एक बैठक हुई, और यहाँ तक कि फ़िलीपींस ने भी दरें बढ़ा दीं, दूसरे देशों ने भी दरें बढ़ा दीं। तो, क्या आपको आईएमएफ, विश्व बैंक की बैठक से कुछ ऐसा मिला था? क्योंकि उस समय भारत समेत दो या तीन उभरते बाज़ारों ने दरें बढ़ा दी थीं।

शक्तिकांत दास

नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मन में कुछ बातें पहले से थीं, अप्रैल की पॉलिसी के समय भी। आईएमएफ जाने से पहले भी हमारी कुछ बातचीत हुई थी। ऐसा नहीं है कि दूसरे केंद्रीय बैंक जो कर रहे हैं, हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे हमें असल में ग्लोबल महंगाई के आकलन को समझने का एक मौका मिला। अलग-अलग केंद्रीय बैंकों के बीच विचारों का काफी आदान-प्रदान हुआ, क्योंकि आईएमएफ के साथ-साथ हमारी केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक हुई; और इससे हमें यह जानने का मौका मिला कि वे अपने देश की और ग्लोबल महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं? तो ज़ाहिर है, आपको वहाँ से कुछ इनपुट मिलेंगे, लेकिन हमारी पॉलिसी हमारे देश के अंदरूनी कारकों के आधार पर तय होती है।

सीएनबीसी टीवी18

जब आप दरें बढ़ाते हैं, तो सभी बैंक बाहरी बेंचमार्क पर होते हैं। इसलिए, दरों में बढ़ोतरी बहुत तेज़ी से लागू होगी। क्या आपको चिंता है कि इससे एनपीए बढ़ सकते हैं? मुझे लगता है कि करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट में भी इस बारे में चिंता जताई गई थी। अचानक दरों में लगातार बढ़ोतरी।

शक्तिकांत दास

कुल एनपीए 6.5 प्रतिशत पर बना हुआ है, और आपने रिटेल सेक्टर के बारे में उल्लेख किया था। करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट में मूल रूप से यह कहा गया था कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे लोगों की सैलरी कैसे आ रही है, ईएमआई और दूसरे पेमेंट कैसे हो रहे हैं। इसलिए, यह एक तरह का संकेत था कि आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए। और जब करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस समय जो आँकड़े उपलब्ध थे, उनके अनुसार सभी बैंकों के रिटेल पोर्टफोलियो में एनपीए का कुल स्तर 2.0 प्रतिशत से ज़्यादा हो गया था। लेकिन उसके बाद, अगली अवधि के लिए हमारे पास जो शुरुआती आँकड़े हैं, उनके अनुसार यह घटकर लगभग 1.8 प्रतिशत या 2.0 प्रतिशत से थोड़ा कम हो गया है। इसलिए, 2.0 प्रतिशत के स्तर पर भी, यह ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत हो। मूल रूप से, इसका मतलब यह है कि यह एक समस्या बन सकती है, और इसलिए इस पर ज़्यादा सावधानी से नज़र रखने और वसूली पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ ही बैंकिंग सेक्टर पर भी। जैसा कि मैंने कहा, कुल एनपीए 6.5 प्रतिशत है। पिछले हफ़्ते, मैंने पब्लिक और प्राइवेट, दोनों सेक्टर के बैंकों के साथ बैठकें कीं। हमने इस पर चर्चा की है, बैंकों को इस बारे में जागरूक किया गया है, और असल में, बैंक एनपीए के स्तरों पर बहुत बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील हैं। लगभग सभी बैंकों में वसूली की दक्षता

में सुधार हुआ है, और वे लगभग 100 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गए हैं। बैंकों ने कोविद काल के दौरान काफ़ी मात्रा में पूंजी जुटाई है। आगे भी, कई बैंकों के पास पूंजी जुटाने के अपने कार्यक्रम हैं। और आपने एक और सवाल पूछा था कि क्या दरों में बढ़ोतरी का क्रेडिट ऑफ़टेक (ऋण उठाव) पर कोई नकारात्मक असर पड़ेगा। क्रेडिट ऑफ़टेक कई कारकों पर निर्भर करता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था कैसा प्रदर्शन कर रही है, और निजी उपभोग तथा निजी मांग में किस तरह से तेज़ी आ रही है। इसलिए, यह कई जटिल कारकों का मेल है; और अर्थव्यवस्था के बुनियादी आधार जिस स्थिति में हैं, तथा विकास में सुधार के जो स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं—जैसे कि PMI के आंकड़े और अन्य बातें जिनका मैंने उल्लेख किया - उन्हें देखते हुए, मुझे लगता है कि कोविद और उसके ऊपर युद्ध की स्थिति के बावजूद, बैंक क्रेडिट की मांग स्थिर बनी रहनी चाहिए। मेरे पास 6 या 7 मई तक के जो ताज़ा आंकड़े हैं, उनके अनुसार बैंक क्रेडिट में वृद्धि लगभग 11 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष है, जो पिछले साल की तुलना में दोगुनी से भी ज़्यादा है। दोगुनी से ज़्यादा होने का मतलब है वृद्धि दर। पिछली बार यह लगभग 5-6 प्रतिशत थी; अब, हम 11 प्रतिशत पर हैं।

सीएनबीसी टीवी18

बैंकों का कहना है कि इसका कुछ श्रेय महंगाई को भी जाता है, जिसके कारण कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें बढ़ गई हैं। मैं असल में आपसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के बारे में पूछना चाहता था। क्या आरबीआई इस बात से सहमत होगा कि बैंक बीमा क्षेत्र में 30 प्रतिशत से ज़्यादा हिस्सेदारी रखे? क्योंकि अन्य मामलों में आपने यह शर्त रखी है कि हिस्सेदारी को घटाकर 30 प्रतिशत से नीचे लाया जाना चाहिए।

शक्तिकांत दास

किसी एक मामले पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी ने आरबीआई को विलय का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई में इसकी जांच चल रही है। इसलिए, जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता और उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता, तब तक इस पर मेरी तरफ से कुछ भी कहना सही नहीं होगा। और एक और बात, माफ कीजिए, मैं बताना भूल गया था - सरकारी उधारी कार्यक्रम के संदर्भ में - हमने अपनी एचटीएम की ज़रूरत को बढ़ाकर 23 प्रतिशत कर दिया है। तो, ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने उधारी की तरफ से आंखें मूंद ली हैं। यह मामला पूरी तरह से हमारे सामने है। तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मामला अभी जांच के दायरे में है, और हम जल्द ही किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे।

सीएनबीसी टीवी18

अभी और भी कई सवाल बाकी हैं, लेकिन मेरे पास समय खत्म हो गया है। बस क्रिप्टो पर आखिरी बात। इसका रेगुलेशन अभी तक नहीं आया है। यह एक तरह से बीच में ही अटका

हुआ है। फिर क्वाइनबेस के सीईओ ने कहा कि आरबीआई ने हमें यूपीआई इस्तेमाल करने से मना किया था - इस पर आपका क्या रुख है? क्या यह रेगुलेशन आएगा? यह कब तक आने की उम्मीद है? लोगों को क्रिप्टो के मामले में कब तक पूरी तरह से स्पष्टता मिल पाएगी?

शक्तिकांत दास

बाहर के लोगों द्वारा की गई अटकलबाज़ियों पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगा। क्रिप्टो के संबंध में, हम लगातार इसके बारे में आगाह करते रहे हैं, और अब आप देख ही सकते हैं कि क्रिप्टो बाज़ार का क्या हाल हुआ है। अब, अगर हम इसे रेगुलेट कर रहे होते - या कोई और रेगुलेटर इसे रेगुलेट कर रहा होता - और उसके बाद बाज़ार क्रैश हो जाता, तो ज़ाहिर है, लोग यह सवाल उठाते कि रेगुलेशन का क्या हुआ? इसलिए, यह एक ऐसा उत्पाद है जिसका कोई भी 'अंडरलाइंग एसेट' (मूल आधार) नहीं है। इसे रेगुलेट कैसे किया जाए - इस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्रिप्टो पर हमारा रुख बिल्कुल साफ है। यह भारत की मौद्रिक, वित्तीय और मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता को गंभीर रूप से कमज़ोर कर सकता है। और हम अपने इसी रुख पर कायम हैं। हमने सरकार को अपना पक्ष बता दिया है, और सरकार इस पर सोच-समझकर फ़ैसला लेगी। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ़ से जो बातें और बयान आ रहे हैं, वे काफ़ी हद तक हमारे विचारों से मेल खाते हैं। वे भी इस मामले को लेकर उतने ही चिंतित हैं।

सीएनबीसी टीवी18

गवर्नर साहब, आपने मुझे उम्मीद से कहीं ज़्यादा समय दिया है। मैक्रोइकोनॉमी पर इस विस्तृत बातचीत के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

शक्तिकांत दास

धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। धन्यवाद।